

Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्गा
0788-4030383, 3293199
भगतान के वस्त्र, श्रृंगार
मूर्तियां एवं समस्त
पूजन सामग्री
संगमरमर व पीतल की
मूर्तियां राशि रत्न
एवं उपरतन उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय



रायपुर, दुर्गा एवं जगदलपुर से प्रकाशित

दर्शन

दुर्गा राहर में
सुप्रसिद्ध
ज्योतिषाचार्य
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय
सिकोला भाठा, सब्जी मार्केट के
सामने, धमधा नाका, दुर्गा

वर्ष 15, अंक 144 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

दुर्गा, शुक्रवार 17 अप्रैल 2026

www.samaydarshan.in

दुनिया के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करेंगे भारत और ऑस्ट्रिया: प्रधानमंत्री मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नयी ऊर्जा आयेगी और ऑस्ट्रिया की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता तथा भारत की गति और पैमाना दुनिया के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करेगा।
दोनों देश रक्षा, सेमीकन्डक्टर, क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और माइग्रेसन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को नर्सिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के



तहत हॉलिडे प्रोग्राम शुरू करने की भी घोषणा की है। मोदी ने भारत यात्रा पर आये स्टॉकर के साथ वार्ता के बाद गुरुवार को यहां संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी को नवाचार

विशेष संसद सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गुरुवार से शुरू हो रहा संसद का विशेष सत्र देश में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में एक 'ऐतिहासिक कदम' है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की गरिमा और प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, संसद के आज के विशेष सत्र से हमारा देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं और बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है।
एशिया में स्थायी शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के प्रबल समर्थक हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाना, हमारी साझी प्रतिबद्धता है।

राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने उपाध्यक्षों के पैनेल का पुनर्गठन किया

6 सदस्यों में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम भी शामिल

रायपुर। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उपाध्यक्षों के पैनेल (उपसभापतियों की समिति) का पुनर्गठन किया है। उपाध्यक्षों के पैनेल में बीजेपी, कांग्रेस, AIADMK और बीजेडी के छह सदस्यों को नामित किया गया है। समिति छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम भी शामिल किया गया है। पुनर्गठित पैनेल में फूलो देवी नेताम के अलावा बीजेपी से दिनेश शर्मा, एस फांगनोन कोन्यक और घनश्याम तिवारी AIADMK से एम. थंबोदुरई; और बीजेडी से सस्मित पात्रा शामिल हैं।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, 'राज्यसभा के सभापति ने 15 अप्रैल 2026 से उपसभापतियों की समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें



दिनेश शर्मा, एस फांगनोन कोन्यक, एम थंबोदुरई, सस्मित पात्रा, फूलो देवी नेताम और घनश्याम तिवारी जैसे सदस्य शामिल हैं। उपसभापति के रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह को इस पद के लिए फिर से मनोनीत किए जाने की संभावना है। हरिवंश नौ अप्रैल को अपनी सेवानिवृत्ति तक लगातार दो कार्यकालों के लिए राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं।

लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा सदस्य पद की शपथ ली, सीएम साय ने दी बधाई

छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ भाजपा नेत्री लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा सदस्य पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री साय ने हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। और कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप छत्तीसगढ़ की शक्ति आवाज बनकर प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ संसद के उच्च सदन में रखेंगी। आपका समृद्ध राजनीतिक अनुभव विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है जनगणना : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर नागरिकों को इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी आज से ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक



और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों

घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे।
उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी प्रणाली पर आएँ, तो उन्हें सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं नीतिगत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य मतदान की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा- नागरिकों को वोट के लिए मजबूर नहीं कर सकते

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य मतदान लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो लोग मतदान करने से इनकार करते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि चुनावों में भागीदारी को दमकारी या बाध्यकारी उपायों से लागू नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश

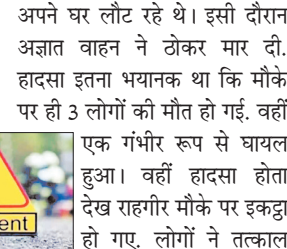


सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों से मताधिकार प्रयोग करने की अपेक्षा होती है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया था कि अदालत चुनाव आयोग को अनिवार्य मतदान के लिए दिशानिर्देश बनाने और बिना वैध कारण वोट न देने वालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समिति गठित करने का

निर्देश दे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मताधिकार के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उद्योग मुद्दे नीतिगत दायरे में आते हैं और इन पर उचित विधायी और कार्यकारी अधिकारियों (संसद और सरकार) द्वारा विचार किया जाना ही सबसे बेहतर है।
पीठ ने दोहराया कि मतदान एक संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक कर्तव्य है।

रफ्तार ने रोकी सांसें: अज्ञात वाहन ने 4 बाइक सवारों को मारी ठोकर, 3 की मौत

कानपुर। जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 4 बाइक सवारों को ठोकर मार दी। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं हादसा होता देख राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।
बता दें कि घटना बिल्हौर के शिवराजपुर में दुबियाना अंडरपास के ऊपर हाइवे पर उस वक्त घटी, जब 4 बाइक सवार अपनी भांजे के तिलक कार्यक्रम में शामिल होकर



अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं हादसा होता देख राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए भिजवाया। वहीं तीनों मृतकों की लाश का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा। मृतकों की पहचान विनोद निषाद (45), रामनारायण (52) और पिपूष निषाद (11) के रूप में हुई है।

आग में मौत का तांडव : 10 से ज्यादा सिलेंडर फटे, आगजनी से 2 की मौत

लखनऊ। विकासनगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम झुग्गी-झोपड़ियों में हुई आगजनी की घटना में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ये घटना बुधवार शाम की है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर फटने के बाद ये आग लगी। आगजनी में 50 से ज्यादा झुग्गीजलकर खाक हो गईं। इधर आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर डटे रहीं। जैसे जैसे आग पर काबू पाया गया। दूसरी ओर एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों को खाली कराकर कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति रोक दी गई। जानकारी के मुताबिक आग



की लपटें 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपना सामान बचाने तक का मौका नहीं मिला। भयंकर धमाके के बीच 50 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए, दुर्घटना को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता व्यक्त हुए जिलाधिकारी से बात की और प्रभावितों को हरसंभव मदद देने को कहा।

तेहरान में मौजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका-ईरान वार्ता के दूसरे दौर के लिए बनाया दबाव

तेहरान। अमेरिका से मिले एक नए संदेश के साथ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के प्रयास में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता के एक नए दौर की संभावना पर ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है।
सात अप्रैल को शुरू हुआ दो सप्ताह का नाजुक युद्धविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। इस्लामाबाद में रविवार को बिना किसी समझौते के समाप्त हुई प्रारंभिक वार्ता के बाद पाकिस्तान आगे की वार्ता के लिए समन्वय कर रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मध्यस्थता



प्रयासों में शामिल हैं जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ राजनयिक वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए चार दिवसीय खाड़ी दौरे के पहले पड़ाव के रूप में सऊदी अरब में हैं। पाकिस्तानी अधिकारी दूसरे दौर की वार्ता के लिए युद्धविराम को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं और क्षेत्रीय साझेदारों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अमेरिका पर प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करें

जिससे कोई राजनयिक गलती न हो। यह राजनयिक प्रयास अमेरिका और ईरान को नौसैनिक नाकाबंदी के कारण बढ़े तनाव के बीच किया जा रहा है जो क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहा है। हालांकि इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते की दिशा में संभावित प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष में अब तक लगभग 3,000 लोग मारे गए हैं और यह पश्चिम एशिया में फैल गया है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को उस समय और गति मिली जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले 'अद्भुत दो दिनों' का वर्णन किया, जिससे संकेत मिला कि ईरान के साथ युद्ध अपने अंत के

करीब हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि समझौते की संभावनाएं आशाजनक लग रही हैं। इसके बावजूद, अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी की हुई है और वह मौजूद, सतक और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं।
ईरानी सेना ने इस नाकाबंदी को युद्धविराम का उल्लंघन बताया है और बुधवार तक इसके कारण नौ जहाजों को वापस लौटना पड़ा है। ईरान के संयुक्त सैन्य कमाण्डर अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है तो तेहरान लाल सागर, खाड़ी और ओमान सागर के रास्ते व्यापार अवरुद्ध करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

हमारी जनगणना हमारा विकास

(जनगणना 2027 का पहला चरण)
स्व-गणना (Self Enumeration) से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर (भाग-1)

स्व-गणना क्या है?

स्व-गणना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप प्रणाली की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं SE पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं

- क्या स्व-गणना अनिवार्य है? नहीं, यह अतिरिक्त सुविधा है, यदि आप स्व-गणना नहीं करते तो प्रणाली आपके घर आकर जानकारी दर्ज करेगा
- क्या मैं किसी भी भाषा में स्व-गणना कर सकता / सकती हूँ? यह सुविधा हिंदी, अंग्रेजी और 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है
- क्या स्व-गणना के लिए इंटरनेट जरूरी है? हाँ, पोर्टल तक पहुँचने और जानकारी भरने के लिए इंटरनेट आवश्यक है
- क्या मेरी जानकारी सुरक्षित है? हाँ, सभी डेटा सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और सरकारी सर्वरों में संरक्षित है
- SE ID क्या है और इसका उपयोग क्या है? सबमिशन के बाद आपको एक विशिष्ट 11 अंकों की SE ID मिलेगी (SMS / email से), जिसे प्रणाली के आने पर उन्हें दिखाना आवश्यक होगा
- यदि SE ID भूल जाऊँ तो क्या करूँ? पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से SE ID पुनः प्राप्त की जा सकती है
- क्या स्व-गणना के बाद भी प्रणाली आएगा? हाँ, प्रणाली आपके घर आएगा और SE ID के आधार पर जानकारी की पुष्टि करेगा
- क्या मुझे कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है? नहीं, किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है
- क्या पोर्टल पर सहायता उपलब्ध है? हाँ, पोर्टल पर, यूज़र गाइड, फ्लोचार्ट, ट्यूटोरियल वीडियो, FAQs और टूलटिप्स के रूप में सहायता उपलब्ध है

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी

टोल फ्री - 1855

CensusIndia2027

संक्षिप्त समाचार

अधूरे अंडरब्रिज निर्माण का काम जल्द करो पूरा, नहीं तो होगा 7 दिवस पर उग्र आंदोलन : कांग्रेस



राजनांदगांव। तीन वर्षों से अधूरा पड़ा अंडर ब्रिज पटरीपारवासियों के लिए मुसीबत बन चुका है। इस समस्या पर पुनः रेलवे प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु आज मुख्य स्टेशन प्रबंधक को मंडल अभियंता के नाम से वरिष्ठ पार्षद हफीज खान एवं कांग्रेस नेता आसिफ अली के नेतृत्व में जापन दिया गया। वरिष्ठ पार्षद हफीज खान ने बताया कि विगत 3 वर्षों से अंडर ब्रिज क्रमांक 459 गौरी नगर और 460 स्टेशन पाराम में निर्माण कार्य अधूरा है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य अधूरा होने से उक्त स्थल पर कई बार गंभीर दुर्घटना भी घट चुकी है। कांग्रेस नेता आसिफ अली ने कहा कि पूर्व में भी रेलवे प्रशासन को जापन के माध्यम से अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अवगत कराया जाता रहा है, किन्तु आश्वासन के बाद भी रेलवे का उदासीन रवैया अब भी जारी है। उन्होंने रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी है यदि 7 दिवस के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो पटरीपार के रहवासी रेलवे स्टेशन में उग्र प्रदर्शन और रेल रोको जैसी कार्यवाही भी करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। जापन देते में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद छोटेला रामटेके, पूर्व पार्षद समद खान, अब्बास खान, मंडल अध्यक्ष कृष्णा मेथाम, चंचल देवांगन, विजय यादव, जाकिर खान, ताहिर खान, गोपाल सिन्हा, शेख अनोश, पीटर माथियो, हरीश यादव, राबिन जान, जितेंद्र साहू उपस्थित थे।

भाजपा सरकार की छोटी सोच का परिणाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छोटी साड़ियां बांटना : सुखचंद बेसरा



गरि या बंद। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटी जा रही साड़ियों के आकार में कटौती को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने इसे मातृशक्ति का अपमान बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेसरा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण का ढोल पीट रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग के माध्यम से ऐसी साड़ियां बांटी जा रही हैं जो पहनने योग्य ही नहीं हैं। मानक आकार से काफी छोटी इन साड़ियों ने सरकार के भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की पोल खोल दी है। सुखचंद बेसरा ने कहा कि साड़ियों के कपड़े और लंबाई में कटौती करना सीधे तौर पर करोड़ों रुपये के घोटाले का संकेत है। आखिर किसके इशारे पर टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर छोटी साइज की साड़ियां खरीदी गईं? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर की मेहनती महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिन-रात शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं। उन्हें ऐसी साड़ियां देना जो तन ढकने के लिए भी पर्याप्त न हों उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। यह भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विभाग में ऊपर से नीचे तक कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। घंटिया गुणवत्ता और कम लंबाई का सामान सप्लाई कर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। जिला कांग अध्यक्ष बेसरा ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तत्काल प्रभाव से विभाग इन साड़ियों को वापस लेकर मानक साइज की उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियां वितरित नहीं करता, तो जिला कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी और विभाग का घेराव करेगी। उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। जो सरकार महिलाओं को सम्मानजनक वस्त्र तक उपलब्ध नहीं करा सकती उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम इस साड़ी घोटाले की जांच होने तक चुप नहीं बैठेंगे।

घुमका नगर पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान

सभी 15 वार्डों में मजबूती से लड़ेगी चुनाव : भूपेश तिवारी

राजनांदगांव। आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष भूपेश तिवारी ने घुमका नगर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी आगामी चुनाव में नगर पंचायत घुमका के सभी 15 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरी मजबूती, रणनीति तथा जनसमर्थन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और सदस्यता अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि घुमका नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी।

लोकसभा अध्यक्ष भूपेश तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा स्वच्छ राजनीति, पारदर्शिता और जनसेवा की विचारधारा पर कार्य करती रही है। इसी



परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पार्टी केवल ईमानदार, शिक्षित, कर्मठ और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य नगर पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करना, बेहतर सड़क, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और जनसुविधाएं उपलब्ध कराना है।

भूपेश तिवारी ने कहा कि घुमका की जनता अब पारंपरिक राजनीति से ऊब चुकी है और ईमानदार विकल्प चाहती है। आम

आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। उन्होंने कहा कि घुमका नगर पंचायत के विकास, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर पार्टी का स्पष्ट रोडमैप तैयार है। बैठक के पश्चात पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में सघन सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं, महिलाओं एवं नागरिकों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। भूपेश तिवारी ने कहा कि आने वाले दिनों में घर-घर संपर्क अभियान चलाकर पार्टी का विजन प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाया जाएगा। घुमका नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केवल ईमानदार और योग्य उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। जनता के बीच तेजी से बढ़ रहा आम आदमी पार्टी का जनसमर्थन सदस्यता अभियान से जुड़ रहे युवा, महिलाएं और आम नागरिक विकास,

पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प।

बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश महासचिव वजूद आलम, प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव देविंदर सिंह भाटिया, राजनांदगांव लोकसभा अध्यक्ष भूपेश तिवारी, राजनांदगांव जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोनी एवं खैरागढ़ जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता उपस्थित रहे।

बैठक और अभियान में मुकेश तिवारी, कमलेश स्वर्णकार, आरिफ खान, राजीव कांडू, पूरन यादव, शीतल सिंह बघेल, प्रफुल्ल बैस, एसएस नायडू, नीलेश सोनी, ठकुरी राम, संतोष जंघेल, संतोष यादव, चित्रा गुरुदेव, ईश्वरी प्रसाद साहू, जयदेव (जोजो), किशन निर्मलकर और फगुलाल कुंभकार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही डोंगरगांव और राजनांदगांव क्षेत्र से परमेश्वर साहू, जेनी बाई, हर्षिता सोनी, सरस्वती भद्रा, सुरज डोंगरे, जमुना लाल बोचरे, मिथिलेश हरिहारनो और शुभम रामटेके ने भी अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

केदुवा में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का भव्य उद्घाटन



सरायपाली ग्रामीण (समय दर्शन)। भारतीय जनता पार्टी केदुवा मण्डल क्षेत्र में कृषि एवं सहकारिता को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का नवीन कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, दुर्गापाली (पं. 970) नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति,

कोसमपाली (पं. 968) नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बारडोली (पं. 974) का विधिवत शुभारंभ किया गया।

यह पहल किसानों को सुलभ ऋण, खाद-बीज उपलब्धता एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने में मील का पथर साबित होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मोगरा किशन पटेल, जनपद अध्यक्ष सरायपाली लक्ष्मी हरिचंद्र

पटेल, छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार सदस्य कामता पटेल पिछला वर्ग मोर्चा बिलासपुर प्रभारी धनेश नायक, भाजपा मंडल सरायपाली महामंत्री प्रकाश पटेल, भाजपा केदुवा मंडल अध्यक्ष दण्डधर साव, युवा मोर्चा जिला प्रचार प्रसार सह प्रमुख राजू किर्ती चौहान, किसान मोर्चा केदुवा जलंधर प्रधान, कैलास सरपंच बाराडोली, जयलाल पटेल अध्यक्ष नवरंगपुर सोसाइटी, गोविंद प्रधान, डोलामडी साहू, गुलाब डडसेना, कमल साव, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों की गरिमायुगी उपस्थिति रही, जिससे आयोजन और भी भव्य एवं सफल बना। इस महत्वपूर्ण पहल से क्षेत्र में कृषि विकास को नई गति मिलेगी और किसानों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

गोड़म हिरी पंचायत में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ग्रामीणों का डिजिटल एक्स-रे से जांच

सारागढ़ बिलाईगढ़ टारजन महेश (समय दर्शन) जन-जन का रखे ख्याल, टी.बी. मुक्त भारत अभियान' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्ती से जुटा हुआ है। कलेक्टर डॉ. संजय कुमार कनौजे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (एचआर) डॉ. एफ.आर. निराला के नेतृत्व में जिले में '100 दिवसीय टी.बी. मुक्त भारत अभियान' जोर-शोर से चलाया जा रहा है। 75वीं कड़ी में, खंड चिकित्सा अधिकारी (एचआर) डॉ. आर.एल. सिद्धार के कुशल मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों में विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

शिविरों का विवरण: अभियान के तहत मोबाइल यूनिट के माध्यम से ग्रामीणों के घर के समीप ही एक्स-रे



की सुविधा पहुंचाई जा रही है: ग्राम पंचायत गोड़म: बीते बुधवार को विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

सिद्धार ने बताया कि इस 100 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य टी.बी. के लक्षणों वाले मरीजों की शीघ्र पहचान करना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी को दो सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, शाम को बुखार आना या वजन कम होने जैसे लक्षण दिखें, तो वे तुरंत अपनी जांच कराएं।

कलेक्टर ने बिलासपुर रोड से चारभाटा रोड के प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल का किया निरीक्षण

कार्य को प्राथमिकता के साथ जल्द प्रारंभ करने के लिए निर्देश



मुंगेली (समय दर्शन) जिले के विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिला मुख्यालय स्थित बिलासपुर रोड से चारभाटा रोड के प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्य को प्राथमिकता के साथ जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सड़क निर्माण के लिए भूमि का सीमांकन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पहले सभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएं। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े अधिकारियों को स्टेटमेंट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि योजना के तहत कार्य को स्वीकृति मिलते ही तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि यह

सड़क क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके निर्माण से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। वर्तमान में लोगों को आवागमन में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वह इस सड़क के बन जाने के बाद काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण में सभी मानकों का पालन किया जाए और कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। साथ ही

स्थानीय नागरिकों से भी संवाद बनाए रखने की बात कही, जिससे निर्माण कार्य के दौरान उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने कलेक्टर को कार्य की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना की जानकारी दी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की सलाह दी, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। जिले में सड़क निर्माण जैसे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल ऑडियो में पैसे के लेन-देन की बातचीत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना गरियाबंद में पदस्थ उप निरीक्षक अजय सिंह को किया गया, निलंबित

गरियाबंद। सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो में एक पुलिस अधिकारी द्वारा पैसे के लेन-देन की बातचीत किया जा रहा है। ऑडियो में सुनाई दे रहे पुलिस अधिकारी की आवाज कोतवाली गरियाबंद में पदस्थ उप निरीक्षक अजय सिंह का होना प्रथम दृष्टिया स्पष्ट है। जिस पर पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक अजय सिंह थाना गरियाबंद को पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में जिम्मेदार पद पर कार्यरत रहने के बावजूद पदवी कर्तव्यों के प्रति संदिग्ध आचरण, स्वेच्छाचरिता एवं अनुशासनीयता पाये जाने से उप निरीक्षक अजय सिंह थाना गरियाबंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

लोक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण में भारी अनियमितता, जांच की मांग

अनुबंध वर्ष 2025-26 पूर्ण होने के बाद कार्य अधूरा, 3 माह का अतिरिक्त समय दिया ठेकेदार को

सागरपाली (समय दर्शन)। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ग्राम कापुडीह से बोरमलीहाडीपा, बिरसिंगपाली में नए सड़क मार्ग जो 2.5 किलोमीटर, लागत 2.89 करोड़ में बन रहे डामर रोड निर्माण को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बर्तती जा रही है और शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।

बसना विकासखंड के ग्राम पंचायत कापुडीह से बरमलीहाडीपा, बिरसिंगपाली मार्ग पर नए सड़क निर्माण के दौरान सामग्री का उपयोग निर्धारित मात्रा में नहीं किया जा रहा है एवं ग्रामीणों का कहना है कि जहां सड़क निर्माण में रोलर का पर्याप्त उपयोग होना चाहिए वहां इसका उपयोग कम किया गया है और डामर की परत भी सही तरीके से नहीं डाली जा रही है, इससे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।



ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सड़क से जुड़े पुल निर्माण में भी लापरवाही देखी गई है। सरपंच मीरा पटेल ने बताया कि पुल को डस्ट और बजरी से तैयार किया गया है, जो पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त होने की आशंका हो रही है। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट पर सुरक्षा के लिहाज से टर्निंग वॉल (हूड 2इंच) बनाने की बात कही गई थी, लेकिन उसे

सड़क के नीचे बना दिया गया, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। सड़क के किनारे स्थित तालाब के पास सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि इसकी आवश्यकता थी। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान मिट्टी कटाव से सड़क को नुकसान पहुंच सकता है और वहीं सड़क किनारे पीपल का पेड़ भी झुका हुआ है, जिसकी

निर्माण कार्य भी नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ ही सड़क निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और टिकाऊ सड़क सुविधा मिल सके। लोक निर्माण विभाग स्लूह को फेन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मामले में संज्ञान लिया जाएगा और आगे देखा जाएगा। लोक निर्माण विभाग सब इंजीनियर-मुकेश नायक- ठेकेदार को तीन माह का अतिरिक्त समय दिया गया है कार्य पूर्ण करने के लिए, गुणवत्ता पूर्ण कार्य के लिए संज्ञान लिया जाएगा।

ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर मुम्बई तथा भवानीपटना में कमिश्नरेंट पुलिस की दबिश

20 आरोपी गिरफ्तार, 03 पैनल नेटवर्क ध्वस्त

रायपुर। लगातार रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव कुमार शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले द्वारा सभी अधिकारियों को आईपीएल के दौरान क्रिकेट सट्टा पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। लगातार एण्टी फ्रॉड एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हो रही थी कि शहर के सभी बड़े-बड़े सट्टा खेलने वाले आपस में एक होकर देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहे हैं। दिनांक 13.04.2026 को एण्टी फ्रॉड एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन के पास चारपहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट



मनदीप सिंह निवासी टाटीबंध आमानाका रायपुर बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके मोबाइल फोन को चेक करने पर उसके द्वारा ऑनलाइन बैटिंग साईट्स 3ईन्ड्रै के माध्यम से आई.डी. बनाकर एवं आई.डी. वितरण कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलना/खेलाना पाया गया तथा मनदीप सिंह के पास नगदी रकम भी होना पाया गया। साथ ही

देवांगन की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। मौके से उससे नगदी रकम 20,000/- रुपये जब्त किया गया, पूछताछ में उसने बताया कि मुम्बई में हर्ष नागदेव अपने साथियों के साथ मिलकर बजरंग ग्रुप एप का संचालन कर रहा है साथ ही साथ दुर्गा के हरीश नायक और सनी देवांगन उड़ीसा में रह रहे खुमान साहू के साथ मिलकर उड़ीसा के भवानीपटना में रेड्डी पैनल का संचालन कर रहे हैं। उपरोक्त जानकारी पर एण्टी फ्रॉड एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस को संयुक्त टीम द्वारा रेड कार्यवाही की गई।

प्रकरण 01 मुम्बई रेड - मुम्बई रेड कार्यवाही में टीम द्वारा रेड करने पर मौके से हर्ष नागदेव सहित कुल 09 आरोपी मिले जो बजरंग ग्रुप एप के

संक्षिप्त समाचार

गांव में ही मिला न्याय



रायपुर। धमतरी जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ और डूबान प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाने की दिशा में किया जा रहा नवाचार अब प्रभावी परिणाम देने लगा है। जीप/प्रशासन के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत भवन अकलाडोंगरी में आयोजित लिंक कोर्ट के माध्यम से आज कई राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। लिंक कोर्ट की कार्यवाही में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन लेकर पहुंचे। पीठासीन अधिकारी ने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ सुनवाई करते हुए जूट सुधार के 3 मामलों का तत्काल निराकरण किया। इसके अलावा फौती नामांतरण के 2, ऋय-विक्रय आधारित नामांतरण के 2, भूमि सीमांकन का 1 तथा खाता विभाजन का 1 नया आवेदन प्राप्त हुआ। आज की कार्यवाही की खास उपलब्धि एक जटिल और विवादित नामांतरण प्रकरण का स्थानीय स्तर पर समाधान रहा। इस मामले में सभी 12 हितबद्ध पक्षकारों के बयान मौके पर ही दर्ज किए गए, जिससे लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को गति मिली और अनावश्यक विलंब समाप्त हुआ।

मछली पालन और बहुफसली खेती से बदली तकदीर



रायपुर। ग्रामीण विकास की दिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहकर स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। इसका जीवंत उदाहरण अरौंद डुबान क्षेत्र के ग्राम कलारबाहरा निवासी सगनू राम की प्रेरक सफलता कहानी है।

थाना कबीर नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते 02 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर पुलिस द्वारा जुआ, सट्टा एवं ऑनलाइन सट्टेबाजी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत DCP West श्री संदीप पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में थाना कबीर नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति रेलवे पटरी के पास संधिग्रह रूप से मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट मैचों पर सट्टा खिला रहे हैं। सूचना की पुष्टि हेतु पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से नगद राशि एवं मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

सगनू राम एक छोटे कृषक परिवार से हैं। सीमित भूमि और वर्षा आधारित खेती के कारण उनकी आय अस्थिर रहती थी। सिंचाई की सुविधा न होने से वे वर्ष में केवल एक ही फसल ले पाते थे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती थी। परिस्थितियों में बदलाव तब आया जब उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा योजना की जानकारी मिली। उन्होंने वर्ष 2023-24 में अपने खेत में 25म25 मीटर की डबरी निर्माण के लिए आवेदन किया, जिसे स्वीकृति मिली। लगभग 2.98 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस डबरी ने उनके खेत में स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कर दिया। डबरी बनने के बाद उनकी खेती में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। अब वे नियमित सिंचाई कर पा रहे हैं, जिससे 2 एकड़ में

सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति रेलवे पटरी के पास संधिग्रह रूप से मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट मैचों पर सट्टा खिला रहे हैं। सूचना की पुष्टि हेतु पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए पकड़ा। आरोपियों के कब्जे

सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति रेलवे पटरी के पास संधिग्रह रूप से मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट मैचों पर सट्टा खिला रहे हैं। सूचना की पुष्टि हेतु पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए पकड़ा। आरोपियों के कब्जे

पारिवारिक विवाद में हत्या का खुलासा -पत्नी एवं बेटी सहित 03 गिरफ्तार

रायपुर। दिनांक 29.09.2025 को थाना डीडो नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी वीरेंद्र भारती गोस्वामी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक के शरीर पर 17 गंभीर चोटें पाई गईं, जिससे मृत्यु होना स्पष्ट हुआ।

इलाज हेतु भेजना परिवार जनों को बताकर गुमराह किया गया घ दर्ज अपराध: थाना DD नगर में अपराध क्रमांक 252/2026 धारा 103(1), 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डीसीपी पश्चिम श्री संदीप पटेल के मार्गदर्शन, एडिशनल डीसीपी श्री राहुल देव शर्मा के पर्यवेक्षण में एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण की गहन जांच एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी, पुत्री एवं नाबालिग से पूछताछ की गई। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 27.09.2025 की रात लगभग 11 बजे मोबाइल देखने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में आरोपियों ने आक्रोश में आकर घर में रखे लकड़ी के बेट एवं ईंट से मृतक के

सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात आरोपियों द्वारा साक्ष्य छिपाने हेतु खून साफकिया गया तथा उपयोग किए गए वस्त्र एवं हथियार (लकड़ी व ईंट) को पास के नाले में फेंक दिया गया। एवं एक राय होकर बाथरूम में गिरकर बेहोश होने से

तकनीकी पहलुओं की जाँच एवं एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश

लखनलाल देवांगन ने किया वेदांता पावर प्लांट के घटनास्थल का निरीक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग, श्रम, सार्वजनिक उपक्रम एवं आबकारी विभाग के मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज सकी जिले के डभरा ब्लॉक के ग्राम सिंघोतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मृत श्रमिकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मंत्री श्री देवांगन ने सिंघोतराई में ही कलेक्टर श्री अमृत विकास टोपनो, पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर तथा वेदांता प्रबंधन के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने श्रम कानूनों के अनुरूप घटना के तकनीकी पहलुओं की गहराई से जाँच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में वेदांता प्रबंधन के चीफ हेड ऑफ ऑपरेशन श्री



सुशील बेहरा ने घटना से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान बाँयलर विशेषज्ञ श्री गुंजन शुक्ला ने हादसे की प्रारंभिक संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। मंत्री श्री देवांगन ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि जाँच पूरी सतर्कता और सूक्ष्मता से की जाए तथा प्रभावित परिवारों को मुआवजा, रोजगार और दुर्घटना में दिव्यांग होने की स्थिति में पेंशन जैसी सुविधाएँ

एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने वेदांता पावर प्लांट दुर्घटना में घायल मजदूरों से मुलाकात की, जो रायगढ़ जिले के विभिन्न अस्पतालों में उपचाररत हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल, एपेक्स हॉस्पिटल, मेड्रो हॉस्पिटल तथा जिनदलङ्कोर्टिस हॉस्पिटल पहुँचकर घायलों का हालचाल जाना, परिजनों से चर्चा की और शासन की ओर से सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी। मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को घायलों के बेहतर और निरंतर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों को आश्वस्त किया कि कंपनी के मुआवजे के अतिरिक्त प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते, आपका उपचार सतत रूप से चलता रहेगा।

औषधीय पौधों की खेती से महिलाओं के जीवन में आया बदलाव

रायपुर। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार और बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के नेतृत्व में वन विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा राज्य में हबल खेती को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुद्देयक उद्देश्य ग्रामीण किसानों, विशेषकर महिलाओं की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इन्होंने प्रयासों के तहत एक अभिनव पहल के रूप में पंचायतों के चारगाहों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। औषधि पादप बोर्ड द्वारा के अंतर्गत बाजार की मांग और बेहतर कीमत को ध्यान में रखते हुए बच, ब्राह्मी, पचौली, पामारोजा, खस और लेमनग्रास जैसे पौधों का चयन किया गया है। इस योजना की सफलता की एक प्रेरक कहानी धमतरी जिले के पंचपेड़ी गांव से सामने आई है। यहाँ के चारगाह क्षेत्र को महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से औषधीय खेती के मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 5.5 एकड़ भूमि में विभिन्न पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें बच, लेमनग्रास, पामारोजा, खस, ब्राह्मी और पचौली शामिल हैं। बोर्ड द्वारा महिलाओं को इस खेती का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें निःशुल्क पौधे भी उपलब्ध कराए गए। इसके बाद महिलाओं ने समूह के रूप में मिलकर खेती शुरू की। आज यह चारगाह न केवल उत्पादन का केन्द्र बन चुका है, बल्कि किसानों के प्रशिक्षण और सीखने का भी प्रमुख स्थान बन गया है। पंचपेड़ी का यह मॉडल अब आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है। किसान यहाँ आकर औषधीय पौधों की खेती की तकनीक सीख रहे हैं और इसे अपनाते के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जल्द ही धमतरी जिले के कोटागांव में भी इस तरह की खेती शुरू की जाएगी। इस नवाचार योजना के माध्यम से चारगाहों का बेहतर उपयोग हो रहा है और महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।



संपादकीय

आत्म-निरीक्षण का विषय

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के लिए यह आत्म-निरीक्षण का विषय होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मसलों में आज भारत की कोई भूमिका क्यों नहीं बची है? फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों अलग-थलग नजर आया? जब ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री भाग नहीं लेंगे, तो ईरान युद्ध पर बुलाई गई सर्वदलीय महज रस्म-अदायगी भर रह गई। ऐसी बैठकों की तभी अहमियत होती है, जब उनका मकसद उत्पन्न परिस्थिति पर पूरी पारदर्शिता बरतते हुए सभी पक्षों के बीच आम-सहमति बनाना होता है। ऐसा तभी हो सकता है, जब देश के शीर्ष नेता बैठक में उपस्थित रहें। और सिर्फ तभी किसी संकट काल में पूरा देश एक स्वर में बोल सकता है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसी राष्ट्रीय एकजुटता दुर्लभ होती चली गई है। नतीजतन, सर्वदलीय बैठकें सियासी नैरेटिव को प्रचारित करने का एक और मौका बन जाती हैं। यही हाल पश्चिम एशिया में युद्ध पर बुलाई गई बैठक का हुआ। विपक्ष ने उसे अपने इस कथानक को बल देने का अवसर बनाया कि मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलताओं ने भारतीय आवाज को गहरी मुसीबत में डाल दिया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत अप्रासंगिक होता जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मध्यस्थ बन कर उभरने की चर्चा हुई। तो उस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हैरतअंगेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं कर सकता! अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों मध्यस्थ बनाया और ये भूमिका स्वीकार कर पाकिस्तान ने क्या जोखिम मोल लिए हैं, ये दीगर सवाल हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को दलाली बताना अपनी विदेश नीति की घोर विफलता से पैदा हुए असंतोष का ही इजहार समझा जाएगा। वरना, कोरिया युद्ध, कान्गो युद्ध, श्रीलंका के गृह युद्ध आदि में मध्यस्थता का भारत के बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद और कूटनीतिक समाधान के संदेश दोनों पक्षों को दिए। अतः जयशंकर के लिए यह आत्म-निरीक्षण का विषय होना चाहिए कि आज अंतरराष्ट्रीय मसलों में भारत की कोई भूमिका क्यों नहीं है? बात यहीं तक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह अलग-थलग नजर आया, वह हालिया तजुबां है। इन सवालों पर गौर करने के बजाय दलाल ना होने का झूठ फूख किसी काम का नहीं है। उससे भारतीय जनमत के सिर्फ एक हिस्से को ही बहलाया जा सकता है।

बैटल ऑफ बंगाल (पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव) में भाजपा और ममता की हर स्तर की लड़ाई

अजय दीक्षित

पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव, भारत के अन्य राज्यों के चुनावों की तरह नहीं बल्कि यह 1757 की प्लासी की लड़ाई की तरह है जब मुट्ठी भर क्लाहव की ब्रिटिश फौज ने तीन लाख की बंगाल के बंगाल सिराजुद्दौला को हरा दिया था और मौरा जाफर को बंगाल का नबाब बना दिया था। वर्तमान विधानसभा चुनाव, जो कई आयामों, स्तरों, उद्देश्यों, के लिए शाम दाम, दंड से लड़ी जा रही है। पूरा राज्य बंगाल मय समाचार पत्रों, दृश्य मीडिया के दो फाड़ हो गया है। एक भाग भाजपा के साथ है तो दूसरा तुणमूल कांग्रेस के साथ है। वाकी सीपीएम, कांग्रेस दूसरे दल, केवल औपचारिक भूमिका में है। जहां तुणमूल कांग्रेस ने एस आई आर का मुद्दा उठाया है वहीं भाजपा 15 साल की भ्रष्टाचार, हिंसा, चुपकेतु को मुख्य मुद्दा बना रही है। 1294 संसदीय विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझमे आ गया है कि यह चुनाव पूरे देश से भिन्न है। बस इतना समझ लो कि भाजपा की भवानीपुर की रेली में बैंड बजा रहे दल की भी उसी रात तुणमूल के लठैत से मार मार खुनी खेल खेला। यह एक बानगी है और यह उस पार्टी के खिलाफ हो रहा है जो देश पर शासन कर रही है। पोस्टर वाला, टगें वाला, माइक वाला जो भाजपा के काम कर रहा है उसे तुणमूल कांग्रेस का कोपा के भाजपा बनाना पड़ेगा। बंगाल का विधानसभा चुनाव इतना बोझिल है कि सर्वेक्षक भी हड़प्रभ है क्योंकि कोई भी मतदाता खुल कर आँकत नहीं कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के शीतल पाल सिंह कहते हैं कि असम, केरल, पांडिचेरी की तरह मतदाता पश्चिमी बंगाल में बोल नहीं रहा है क्योंकि उसे अज्ञात भय है। संदीप घोषाल वीरभूमि में कपड़ा व्यापारी है लेकिन चुनाव की बात करने ही तैयार नहीं बस यह कहते हैं कि दीदी ही आएगा। तुड़मूल सरकार ने लोगों को अपनी चाल में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में सुबेदु अधिकारी को आगे कर चुनाव मैदान में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी सभा कर रहे हैं और उनकी सभा में इतनी भीड़ है जो बता रही है कि पश्चिमी बंगाल में ज्वाला भूकंप रही है। लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी ने एस आई आर को मुद्दा बनाया है और पूरे सूबे से 90 लाख मतदाता डिलीट कर दिया है। कोलकाता में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जबकि ग्रेटर कोलकाता से या कहे अंग्रेजी पुरानी स्टेट में 107 सीट हैं 2021 में यहां पर 90 सीट ममता बनर्जी की तुड़मूल ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15 सीट मिली थी सीपीएम कांग्रेस एक एक सीट पर जीती थी। अबकी बार भाजपा इस क्षेत्र से कुछ अच्छा स्कोर कर पा सकती है। मालदा वीरभूमि, मेदिनीपुर, बांकुरा, चौबीस परगना, सहित अनेक जगह पर तुड़मूल, भाजपा में गजब की टक्कर है। आजादी के बाद पश्चिमी बंगाल में विधान चंद्र राय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उन्होंने आजादी के आंदोलन बहुत ही सराहनीय काम किया। 1977 तक कांग्रेस ही बंगाल की सत्ता में थीं। सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री रहे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में सीपीएम यानी लेफ्ट पार्टियों का समावेश हुआ और वे विधानसभा चुनाव में बहुमत लाने में सफल हुए। ज्योति बसु 27 वर्ष यानि 2000 तक मुख्यमंत्री रहे उनके बाद सीपीएम की विरासत बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में आई 2011 तक 10 वर्ष वह मुख्यमंत्री रहे। 2011 तुड़मूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता में बैठी है। लेकिन अब सीपीएम, सीपीए, आरएसपी, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो बैठी है।

बिहार में विकास सम्बन्धी चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा नए सम्राट को!

कमलेश पांडे

बिहार के नए सम्राट को फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज मिला है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, या पूर्व मुख्यमंत्री दम्पति लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, कभी भी चैन पूर्वक राज नहीं कर सके। लिहाजा, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी उन जातीय और साम्प्रदायिक चुनौतियों से जूझना होगा, जो बिहार के विकास में शुरू से ही बाधक समझी गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक बिहार के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को कांग्रेस के सहयोग से लंबे समय तक राज करते हुए जनसेवा का मौका मिला, वैसी ही मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा के सहयोग से जनसेवा का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा भी है कि पार्टी ने उन्हें पद नहीं, जनसेवा का अवसर दिया है, इसलिए विकास, सुशासन और समृद्धि उनके शासन का मूलमंत्र होगा।

बिहार के आर्थिक विश्लेषक बताते हैं कि बिहार के विकास में श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी रेखा खींचने की कोशिश की, प्रगति नजर भी आई, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और हाल के वर्षों में उत्तरप्रदेश के विकास को देखा जाए तो अब भी बिहार के विकास में कई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ बाकी हैं, जो आंकड़ों और राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखने पर साफदिखती हैं। इसलिए भाजपा की सरकार के सुलझे हुए और समावेशी प्रवृत्ति वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी बिहार के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित चुनौतियों से जूझना होगा। लेकिन अपने मुद्दु स्वभाव से ये एक एक करके इनसे पार पा जाएँगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है।

पहला, निर्धनता, रोजगार और मानव पूँजी के नजरिए से विकास— आंकड़े बताते हैं कि बिहार, भारत के सबसे कम आय वाले राज्यों में शुमार है, जहां गरीबी दर अभी भी काफी ऊँची है और रोजगार की गुणवत्ता कमजोर है। समझा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कम होने के कारण यहां की मानव पूँजी कमजोर है— साक्षरता और स्कूल



लेवल अभी भी देश के स्तर से काफी नीचे हैं, जिससे युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिलने में दिक्कत होती है। ऐसे में यदि अपराध, जातीय सोच और सांप्रदायिक मिजाज को हतोत्साहित करके इन लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसके लिए अप्रवासी बिहारियों और बिहार मूल के एनआरआई को आकर्षित करने वाली योजनाओं को बनाना होगा और उनपर दृढ़तापूर्वक अमल करना होगा।

दूसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के चलते उत्पादकता बढ़ाने पर देना होगा ध्यान— यद्यपि हार की आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन उत्पादकता और आय दोनों ही अपेक्षाकृत कम हैं। ऐसा इसलिए कि उत्तर बिहार 4 महीना बाढ़ से आक्रांत रहता है और तभी दक्षिण बिहार सूखा से जूझ रहा होता है। खेती और बागवानी यहां पर होती तो है, लेकिन भंडारण सुविधाएँ, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और बारहमासी सिंचाई की सीमित पहुँच जैसे कारकों के कारण कृषि अभी भी बहुत जोखिम भरी और कम लाभ वाली काम साबित होती है। लिहाजा किसानों और मजदूरों के बच्चे परदेश कमाने चले जाते हैं और अपनी उद्यमिता से सबको सुख पहुंचाते हैं।

तीसरा, औद्योगिक विकास और निवेश की दिक्कत सबसे बड़ी अड़चन— बिहार में 26 साल

पहले हुए राज्य विभाजन के बाद औद्योगिक आधार छोटा हुआ है, क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योग-धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए। ततपश्चात छोटे और कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग तकनीकी पिछड़ेपन और वित्तीय अभाव के कारण इनका समग्र विस्तार नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। इस कारण और निजी निवेश की दृष्टि से बिहार अभी भी निवेश अनुकूल राज्यों की पहली पंक्ति में नहीं है, बल्कि तेजी के साथ उद्योग बढ़ाने की चुनौती बरकरार है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को चाहिए कि वह महाराष्ट्र और गुजरात की नज्द पर बिहार-उत्तरप्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में औद्योगिक रफ्तार तेज होने से लुक ईस्ट की विदेश नीति को मजबूत आधार मिलेगा।

चौथा, बुनियादी ढांचा और शहरीकरण में निवेश और विस्तार— बिहार में सड़क नेटवर्क, बिजली, जल सुविधा, नालियाँ, जनस्वास्थ्य और शहरी बुनियादी ढांचा अभी भी प्रमुख रूप से कमजोर जगह बनी हुई हैं। चाहे स्थापित शहर हों या कस्बाई शहर, यहां शहरीकरण बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिससे औद्योगिक सेवा अर्थव्यवस्था को उतना बल नहीं मिल पा रहा जितना दूसरे विकसित राज्यों में मिला है। इसलिए नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को

इस ओर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि रोजगार के सृजन में इस क्षेत्र का बड़ा इग्डो होता है।

पांचवाँ, जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर करना— बिहार के शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद कमजोर हैं— खासकर डॉक्टर आबादी अनुपात कम, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है और कुपोषण जैसी समस्याएँ अभी भी गंभीरबनी हुई हैं। इसी तरह पीडीएस (कृषर), राशन, योजनाओं के वितरण में धांधली, रिसाव और कार्यान्वयन की कमजोरी विकास के लाभों को गरीबों तक पहुँचाने से रोकते हैं। इस स्थिति में अमूलचूल बदलाव लाना होगा, ताकि स्थिति बदले।

छठा, शासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर काम ध्यान— बिहारी में जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो शासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें बंधती हैं, लेकिन बाद में सबकुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। अब इस स्थिति को बदलना होगा। क्योंकि कई रिपोर्टों में बिहार को भ्रष्टाचार, निष्पक्ष नियोजन और प्रशासनिक दक्षता की दिक्कत से जूझता हुआ देखा गया है, जिससे बजट का अच्छे तरीके से उपयोग होना मुश्किल होता है। वहीं, कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी निवेश और नागरिक दोनों के लिए चिंता का मुद्दा है। इसलिए नए मुख्यमंत्री को इसे समझना होगा और विशेष टास्क फोर्स का गठन कर इस स्थिति को बदलना होगा। इसी में बिहार का हित निहित है।

सातवाँ, क्षेत्रीय असमानता और जाति धर्म की संवेदनशीलता— अनुभव बताता है कि बिहार में अलग अलग जिलों के बीच विकास का अंतर बढ़ा है; कुछ शहर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र विकास समीक्षा चक्र से बाहर रह जाते हैं। साथ ही, जाति आधारित राजनीति और आरक्षण संबंधी विवाद नीतियों को लंबे समय तक टिकाने और निष्पक्ष ढंग से लागू करने में बाधा बनते हैं। इसलिए सूझबूझ पूर्वक इन चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा। इससे सबका हित संभोग और बिहार विकास के नए कीर्तिमान खड़े करेगा। इस यश नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिलेगा। भाजपा को मिलेगी।

आखिरकार सुनी गई आधी आबादी की आवाज़

आर. विमला, आईएएस

जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो भारत मजबूत होता है। पर की गरिमा से लेकर संसद में समान आवाज़ तक, यह एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की परिकल्पना है। — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की महिलाएँ सदैव महान कर्मा हैं, महिलाएँ अपने ही लोकतंत्र में एक तरह से मेहमान बनकर ही रह गईं। हमारे संविधान ने पहले ही दिन से यह स्वीकार किया था कि जब सदियों से लंबे लंबे अंधकार के तारों से अपने राज्य का शासन चलाया, उसकी बराबरी उनके समकालीन शासक नहीं कर सके। रानी लक्ष्मीबाई साहस की एक अमर मिसाल बन गईं। फिर भी, स्वतंत्र भारत— जो समानता के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक गणराज्य है— ने इन महान महिलाओं की उतराधिकारियों को अपनी विधाधिकारियों में

शायद ही कोई जगह दी। पहली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 4.4 प्रतिशत थी। सात दशक बाद, 17वाँ लोकसभा में भी यह आंकड़ा बढ़कर केवल 14.4 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया। व्यक्तिगत प्रतिभा ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन व्यवस्थागत बदलाव अभी भी नहीं आया था। असल में, महिलाएँ अपने ही लोकतंत्र में एक तरह से मेहमान बनकर ही रह गईं। हमारे संविधान ने पहले ही दिन से यह स्वीकार किया था कि जब सदियों से लंबे लंबे अंधकार के तारों से अपने राज्य का शासन चलाया, उसकी बराबरी उनके समकालीन शासक नहीं कर सके। रानी लक्ष्मीबाई साहस की एक अमर मिसाल बन गईं। फिर भी, स्वतंत्र भारत— जो समानता के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक गणराज्य है— ने इन महान महिलाओं की उतराधिकारियों को अपनी विधाधिकारियों में

2026 तक, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएँ हैं। जिन जगहों पर महिलाएँ शासन करती हैं, वहाँ पानी की आपूर्ति सुचारू होती है, साफ-सफाई की स्थिति बेहतर होती है और लड़कियाँ स्कूल जाना जारी रखती हैं। इसके बावजूद, संसद में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो विधेयक पेश किए गए थे, वे राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दशकों तक बार-बार निष्प्रभावी होते रहे।

वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया— वह अथूरी कड़ी 19 सितंबर 2023 को पूरी हुई। भारत के नए संसद भवन में आयोजित कामकाज के पहले ही सत्र में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद के दोनों सदन में, प्रत्येक राजनीतिक दल के सर्वसम्मति समर्थन से पारित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पेश करते हुए दोनों सदन को बताया— यह कानून

केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय महिला की शक्ति, त्याग और सामर्थ्य के प्रति एक श्रद्धांजलि है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-कोटा भी शामिल है। नए संसद भवन का यह पहला अधिनियम होना अपने आप में एक घोषणा थी— अमृत काल के लोकतंत्र की संरचना पूरे भारत के लिए और सभी की भागीदारी के साथ निर्मित की जाएगी।

इस अधिनियम में बदलाव लाने की अपार क्षमता है, क्योंकि इसके लागू होने से संसद में महिला सदस्यों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। महिला विधायक नितरं स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं—ये वही क्षेत्र हैं, जहाँ

भारत में लैंगिक असमानता सबसे अधिक है। एक ऐसी संसद, जिसमें एक-तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी, वह अलग तरह के प्रश्न पूछेगी और अलग तरह के विचार सुनेगी। इससे भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा, न कि केवल उसकी बाहरी छवि में।

गरिमा से लोकतंत्र तक की यात्रा— हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह समझा है कि ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक सशक्तिकरण खोखला होता है। उनके द्वारा शुरू की गई यह यात्रा अत्यंत बुनियादी गरिमा से लेकर सर्वोच्च लोकतांत्रिक भागीदारी तक एक सुविचारित पथ पर आगे बढ़ती है। इसकी शुरुआत एक शांतिचल से हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए 10 करोड़ घरेलू शांतिचलों ने उन महिलाओं को सुरक्षा और आत्म-सम्मान लाया, जिन्हें लंबे समय से इन दोनों से वंचित रखा गया था।

कूटनीति के जरिए पेट्रोलियम आपूर्ति को रखा बरकरार

उमेश चतुर्वेदी

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पूरी दुनिया की चिंता ऊर्जा को लेकर थी। आज की दुनिया ऊर्जा के लिए जीवाश्म तेलों पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जिसे हम पेट्रोल और डीजल के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस भी आज ऊर्जा की बड़ी स्रोत है। ईरान पर हमले के पहले बहुत लोगों ने होमुर्ज जलडमरूमध्य का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज हर पढ़ा-लिखा और सचेत शख्स इसे जान गया है। फरस को खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान का कब्जा है। इसके जरिए पूरी दुनिया को आपूर्ति होने वाला बौस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ इसी रास्ते से गुजरता रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो ईरान पर हमले के पहले तक भारत आयात होने वाले कच्चे तेल के आधे हिस्से की आपूर्ति इसी रास्ते होती थी। इससे भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक थी। लेकिन भारत ने ना सिर्फ होमुर्ज के जरिए अपनी आपूर्ति को बनाए रखने की कूटनीतिक कोशिशें जारी रखीं, बल्कि वैकल्पिक रास्ते की भी तलाश तेज कर दी। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का करीब 85 फीसद हिस्सा आयात करता है। इसका आधा हिस्सा होमुर्ज के रास्ते ही आता था। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार होमुर्ज के रास्ते भारत रोजाना ढाई से 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता था। लेकिन ईरान पर हमले के बाद यह घटक इसका आधा ही रह गया है। वैसे तो होमुर्ज पर ओमान का भी दावा माना जाता है, लेकिन हकीकत में इस जलमार्ग पर पूरी तरह ईरान का दबदबा है। हमले के बाद ईरान के रिजोव्ल्यूशनरी गार्ड्स ने इस रास्ते पर ना सिर्फ निगरानी बढ़ा दी है, बल्कि सीमित आवाजाही हो ही मंजूरी दी है।

भारत को इसकी आशंका थी, इसलिए उसने खाड़ी के देशों से तेल आयात के लिए वैकल्पिक मार्गों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। संकट के क्षण



में भले ही ईरान ने भारत के प्रति सहयोगी रूख अखिरा कर रखा है, लेकिन भारत ने 'केप ऑफ गुड होप' यानी अफ्रीका के दक्षिण से गुजरने वाले जलमार्ग का भी उपयोग बढ़ा दिया है। इस बीच भारत ने कूटनीतिक प्रयास जारी रखा। इसका असर यह हुआ कि ईरान भारतीय जहाजों को होमुर्ज से गुजरने की अनुमति दे रहा है। एलपीजी लदा एक जहाज कोचीन आ चुका है और ऐसे ही कुछ और जहाज भारत और गैस लेकर भारत आ रहे हैं। इस बीच तेल ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को अपनी नौसेना के जरिए सुरक्षा दे रहा है। भारत सरकार के अनुसार, भारतीय रिफायनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। इस बीच भारत ने रूस से भी कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बढ़ा दी है। इसका असर यह हुआ है कि भारत में जिस तरह की महंगाई की आशंका थी, वैसी नहीं दिखी। हालांकि उद्योगों के लिए आपूर्ति किए जाने वाले व्यवसायिक गैस सिलिंडर को कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तेल की बढ़ती

कीमतों और व्यवसायिक गैस की आपूर्ति कम होने के चलते खाने-पीने वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। महानगरों में सर्वसुलभ ठेले की चाय की कीमतें डेढ़ गुनी तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन आपूर्ति श्रृंखला जारी रहने के चलते स्थिति खराब नहीं हुई है। जबकि पड़ोसी पाकिस्तान में आधी गाड़ियों को ही सड़कों पर उतरने की अनुमति है, वहाँ पेट्रोल भारत के मुकाबले करीब ढाई गुनी ऊंची दर पर मिल रहा है। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद कूटनीति की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभालते हुए युद्ध शुरू होने के महज 48 घंटों के भीतर आठ खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, जार्डन, ओमान, बहरीन और इजरायल के नेताओं से बात की। इसके साथ ही उन्होंने फ्रंस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। इस बातचीत का मकसद वैश्विक हालात पर चर्चा के साथ ही भारतीय हितों को सुनिश्चित करना भी था।

इस बीच 'ग्लोब कोऑपरेशन कार्डिसिल' के महासचिव जासेम मोहम्मद अल बुदैवी से फेन पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बात की है। इस बातचीत का मकसद खाड़ी देशों के इस संगठन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के साथ ही भावी ऊर्जा संकट से भारत को मुक्ति दिलाने की लेकर रणनीति बनाना भी है। इसके पहले मंत्री हरदीप पुरी ने कतर की यात्रा की थी। दरअसल भारत इन देशों से भी पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बढ़ाना चाहता है। भारत की कोशिश ईरान के विकल्प के रूप में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों का भी सहयोग हासिल करने की है।

भारत को अपनी खेती के लिए रासायनिक खाद की भी जरूरत पड़ती है। भारत में खाद उत्पादन के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बेशक रूस से भारत को कच्चा तेल और खाद की सामग्री मिल रही है, लेकिन भारत की कोशिश आपूर्ति को विविधगंभी बनाए रखना है। इसकी वजह यह है कि किसी एक देश पर किसी खास आयात के लिए पूरी तरह निर्भर होना भविष्य में ब्लैकमेलिंग की वजह बन सकता है। भारत के पास आज करीब साठ करोड़ का ऐसा विशाल मध्य वर्ग है, जिसकी खरीद क्षमता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शायद ही कोई उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादक देश ऐसा होगा, जिसे भारत की जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन भारत की अपनी जरूरतें भी हैं और यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे व्यवस्था में अगर किसी चीज की गंभीर कमी होती है तो अफरातफरी का माहौल उत्पन्न होना आसान हो जाता है। इससे महंगाई भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से लोक के बीच नाराजगी बढ़ती है और फिर यह गुस्सा राज व्यवस्था के खिलाफ आंदोलनों के रूप में मुखर होता है। तेल और ईरान संकट को देखते हुए भारत ने कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए जिस तरह अपनी जरूरतों के लायक आपूर्ति का संतुलन बनाए रखा है, वह गौर करने लायक है।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर जनदर्शन में आज 117 आवेदन प्राप्त हुए



राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्ति हेतु ई-केवायसी आवेदन

दुर्ग (समय दर्शन)। जिला कार्यालय के सहायक में आज आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में विभिन्न विभागों से संबंधित 117 आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्व ने जनदर्शन में पहुंचे, जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने हेतु मार्ग दिखाया।

जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने, बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का समय बदलने, राशन कार्ड से नाम हटवाने/जुड़वाने, पानी निकासी हेतु नाली की व्यवस्था, पेय जल एवं तालाबों में निस्सारी पानी भरने संबंधी सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 117 आवेदन प्राप्त हुए।

राशन कार्ड से खाद्यान्न न मिलने के एक प्रकरण में खाद्य विभाग अधिकारी ने आवेदक को अवगत कराया कि खाद्यान्न प्राप्ति हेतु ई-केवायसी आवश्यक है। उन्होंने अवगत कराया कि स्वयं के एनड्राइड मोबाइल पर राशन कार्ड 'ई-केवायसी' डाउनलोड कर आवेदक स्वयं भी ईकेवायसी कर सकते हैं। इस अवसर पर समाज कल्याण नगरी निकाय, खाद्य राजस्व सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

पीलिया प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग का सर्वे अभियान जारी



दुर्ग (समय दर्शन)। वार्ड-67 सेक्टर-7 पश्चिम सड़क 37 ए भिलाई नगर में पीलिया के मरीजों की जानकारी होने पर 15 अप्रैल 2026 को डॉ. मनोज दानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग एवं डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, जिला सर्विलेंस अधिकारी दुर्ग के मार्गदर्शन में श्री विजय सेजुले, सुपरवाइजर, श्री हितेंद्र कोसरे, बीईटीओ एवं स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों के साथ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। आज प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 110 घरों का भ्रमण किया गया, जिसमें कोई भी पीलिया से ग्रसित नए मरीज नहीं मिले। इस प्रकार उक्त संक्रमित क्षेत्र में आज दिनांक तक कुल 37 पीलिया के मरीज मिले, जिनमें से 03 पुराने मरीज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भिलाई में उपचारित हैं। 01 पुराना मरीज पल्स हॉस्पिटल भिलाई से डिस्चार्ज हुए, इस प्रकार कुल भर्ती मरीज 03 है। उक्त प्रभावित क्षेत्र में नगर निगम भिलाई की मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा लक्षणयुक्त मरीजों की CBC/LTF/RFT/Widal व अन्य अतिआवश्यक जांच की जा रही है, वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है।

सर्वे के दौरान पानी नगर निगम भिलाई द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, पाइप लाइन को बदला जा रहा है। बीएसपी भिलाई द्वारा पीलिया प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग डॉ. मनोज दानी, जिला सर्विलेंस नोडल अधिकारी डॉ. सीबीएस बंजारे के द्वारा निरीक्षण किया गया। विकासखंड प्रशिक्षण अधिकारी, राजेंद्र डाहरे रिसाली, रोहित मंडले, पर्यवेक्षक, लेब टेक्नीशियन दीपक चंद्राकर रिसाली, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पंकज राठौर, एमपीडब्ल्यू प्रिंस पीयूष टंडन, रमा शंकर यादव, पंकज राठौर अनिल धीमर उपस्थित रहे। पीलिया हेतु पीलिया प्रदूषित जल व भोजन से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो विषाणुओं के संक्रमण से होता है। विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 15 से 50 दिनों के भीतर बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। पीलिया के प्रमुख लक्षण भूख न लगना, पीले रंग की पेशाब होना, भोजन का स्वाद न आना, उल्टी लगना या होना, सिर में दर्द होना एवं कमजोरी तथा थकावट का अनुभव करना, पेट के दाहिने तरफ ऊपर की ओर दर्द होना, आंखें व त्वचा का रंग पीला होना।

गर्मी व लू से बचाव के लिए प्रशासन की एडवाइजरी

लू के लक्षण और इससे बचाव के उपाय बताते आयोजित होंगे जन जागरूकता कार्यक्रम

गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी सावधानियां

लू लगने पर तुरंत क्या करें?

दुर्ग, (समय दर्शन)। ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2026 को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें लू के लक्षण, लू से बचाव के उपाय, प्रारंभिक उपचार और आवश्यक सावधानियां संबंधी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों को लू के लक्षण, लू से बचाव, लू लगने पर प्रारंभिक उपचार हेतु जनसमुदाय में जागरूकता लाने व प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों में लू से प्रभावित मरीजों का प्राथमिकता से परीक्षण करने के निर्देश भी दिये गये हैं। साथ ही जिले के संबंधित सभी विभागों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लू बचाव/उपाय के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

लक्षण- सिर से भारीपान और दर्द होना, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक हो जाने के बाद भी पसीने का न आना, अधिक प्यास और पेशाब कम आना, भूख कम लगना तथा बेहोश होना।

बचाव के उपाय- लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप और गर्मी से ज्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में पानी और खनिज मुख्यतया नमक की कमी हो जाना होता है। अतः इससे बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए- बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर ना जाए। धूप से निकलने से पहले सर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें। पानी अधिक मात्रा में पीये और अधिक समय तक धूप में न रहें। गर्मी के दौरान नरम मुलायम सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि हवा और कपड़े पसीने को सोखते रहे। इसी प्रकार अधिक पसीना आने की स्थिति में ओ.आर.एस. घोल पीयें। चक्कर आने, उल्टी आने पर छायादार स्थान पर विश्राम करें तथा शीतल पेय जल अथवा उपलब्ध हो तो फल का रस,



लस्सी, मठा आदि का सेवन करें। प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से निःशुल्क परामर्श लिया जाए और उल्टी, सर दर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र से जरूरी सलाह लिया जाए।

लू लगने पर किये जाने वाला प्रारंभिक उपचार- बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठण्डे पानी की पट्टी लगावें, अधिक पानी व पेय पदार्थ पिलावें जैसे कच्चे आम का पना, जल जीरा आदि, पीड़ित व्यक्ति को पंखे के नीचे हवा में लिटा दें, शरीर पर ठण्डे पानी का छिड़काव करते रहें, पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र किसी नजदीकी चिकित्सा केन्द्र में उपचार हेतु ले जाए तथा मितानिन ए.एन.एम. से ओ.आर.एस. के पैकेट हेतु संपर्क करें।

क्या करें- जितना हो सके पर्याप्त पानी पीये, भले ही प्यास न लगी हो। मिर्गी, हृदय, गुर्दे या लीवर से संबंधित रोग वाले जो तरल प्रतिबंधित आहार लेते हो, तरल पदार्थ लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। हल्के, हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहने। ओ.आर.एस. (ओरल रिहाइडेशन) घोल, घर का बना पेय लस्सी, (तोरानी चावल) का पानी, नींबू का पानी, छछ आदि का उपयोग करें। बाहर जाने से बचे, यदि बाहर जाना आवश्यक है, तो अपने सिर (कपड़े/टोपी या छाता) और चेहरे को कवर करें। जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें।

क्या न करें- गर्मी के दौरान बाहर न जाए, यदि आपको आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है तो दिन के शीतलन घंटों के दौरान अपनी सारणी निर्धारित करने का प्रयास करें। अत्यधिक गर्मी के घंटों के दौरान बाहर जाने से बचे (विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच), नंगे पैर या बिना

चेहरे को ढके और बिना सिर ढककर बाहर न जाए। व्यस्ततम समय (दोपहर) के दौरान खाना पकाने से बचे, खाना पकाने वाले क्षेत्रों (रसोई घरों) में दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें, जिससे पर्याप्त रूप से हवा आ सके। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड

पेय, पीने से बचे जो शरीर को निर्जलित करते हैं। उच्च प्रोटीन, मसालेदार और तेलीय भोजन खाने से बचे, बासी खाना न खाए। बीमार होने पर बाहर धूप में न जाए, घर पर रहे।

अन्य सावधानियां- जितना हो सके घर के अंदर रहें। अपने घर को ठंडा रखें-धूप से बचाव के लिए दिन में पर्दे, शटर का उपयोग करें और खिड़कियां खोलें। निचली मंजिलों पर बने रहने का प्रयास करें। पंखों का उपयोग करें, कपड़ों को नम करें और अधिक गर्मी में ठंडे पानी में ही स्नान करें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं-उच्च बुखार/लगातार सिरदर्द/चक्कर आना/मतली या भटकाव/लगातार खांसी/सांस की तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाये। जानवरों को छाया में रखे और उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दें। इन उपायों का उपयोग कर लू एवं हीटवेव के प्रभाव से बचा जा सकता है।

वरिष्ठ नागरिकों और फील्ड स्टाफ के लिए निर्देश
वृद्धजनों और धूप में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी विशेष रूप से गाइडलाइन जारी की गई है, ऐडवाइजरी अनुसार जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनकी नियमित जांच और देखभाल सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि किसी वृद्ध को असामान्य रूप से भूख कम लगना, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी गई है। समाज के हर वर्ग और व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए विस्तृत कार्ययोजना सौंपी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा 'लू कार्य योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं-

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को गर्मी के दौरान सार्वजनिक स्थलों, आश्रय स्थलों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, लू के दौरान बाहरी गतिविधियों और कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में 'ग्रीन कवर' बढ़ाने हेतु छतों पर उद्यान और शहरी वन विकसित करने के प्रयासों को गति दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को ग्रामीण स्तर पर लू से बचाव का प्रशिक्षण आयोजित करने और समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में लू प्रभावित मरीजों के लिए दवाओं व उपचार की विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है। गंभीर स्थिति में सहायता के लिए महतारी एक्सप्रेस (108/104) को उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विद्युत विभाग को भीषण गर्मी और लू की अवधि के दौरान अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और पेयजल आपूर्ति केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों में शीतल पेयजल, ओ.आर.एस. और आइस पैक की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए शिक्षण संस्थानों के समय में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में 'प्याऊ' घरों तथा शुद्ध पेयजल व छछ की व्यवस्था करने को कहा गया है। पुलिस व यातायात कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हल्के रंग की टोपी या छत्री का प्रयोग करने, सनग्लासेस पहनने और पर्याप्त पानी पीने के निर्देश दिए गए हैं। यथासंभव युवा कर्मियों को दिन की यातायात ड्यूटी में तैनात करने का सुझाव दिया गया है। श्रम एवं रोजगार विभाग को उद्योगों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के समय (दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक) बाहरी काम और लू से बचाने के लिए कार्यकालीन समय में परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही, कार्यस्थलों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मजदूरों के लिए 'आइस पैक' (बर्फ की थैली) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

मिशन क्लीन सिटी' के तहत सभी एस.एल.आर.एम. सेंटर क्रियाशील

दुर्ग नगर निगम ने 44 करोड़ के बजट और कचरा निपटान व्यवस्था का दिया विवरण



दुर्ग (समय दर्शन)। नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा 'मिशन क्लीन सिटी' योजना के अंतर्गत शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित एक समाचार के स्पष्टीकरण में निगम प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में सभी एस.एल.आर.एम. सेंटर क्रियाशील हैं। इन केंद्रों की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से मानवीकृत है, जहाँ स्वच्छता दीर्घियों द्वारा वार्डों से प्राप्त कचरे का निपटान हाथ से किया जाता है। व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से समस्त सेंट्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और मशीनीकरण (तकनीकी उन्नयन) का कार्य तेजी से संचालित किया जा रहा है। शहर की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए बुनियादी ढांचे में विस्तार

किया जा रहा है, जिसके तहत शासन से 08 नवीन एस.एल.आर.एम. सेंट्रों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 03 केंद्रों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है और शेष 05 केंद्रों के लिए भूमि चिह्निकन की प्रक्रिया जारी है। साथ ही, एक नए प्रोसेसिंग प्लांट की निविदा प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डीपींग यार्ड में आग लगने जैसी घटनाएं अक्सर कचरे में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों या बाहरी तत्वों की शरारत के कारण होती हैं, जिसे निगम की लापरवाही मानना उचित नहीं है, क्योंकि निगम पूर्णतः 'जोरो वेस्ट' की नीति पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था हेतु आवंटित 744 करोड़ के बजट के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि केवल कचरा फेंकने के लिए नहीं है। इस बजट का उपयोग पूरे शहर की व्यापक सफाई, हजारों सफाई कर्मियों के वेतन भुगतान, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, मशीनों के रख-रखाव और भविष्य के लिए प्रस्तावित वेस्ट-टू-कम्पोस्ट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एडीआर सेमिनार का सफल आयोजन



दुर्ग, (समय दर्शन)। सेठ रतनचंद्र सुराना विधि महाविद्यालय में खंड 02 द्वितीय (चतुर्थ सेमेस्टर) के विद्यार्थियों हेतु Alternative Dispute Resolution विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है विषय पर भी विशेष जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत

की अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के चार न्यायाधीश एवं मीडिएटर अ धि व क ा उपस्थित रहे। अतिथियों का महाविद्यालय परिसर में भव्य स्वागत किया गया, तत्पश्चात न्यायाधीशों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। सेमिनार के दौरान न्यायाधीशों ने विद्यार्थियों को संविधान एवं Alternative Dispute Resolution (ADR) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ADR क्या है, इसका उपयोग किन-किन परिस्थितियों में किया जाता है, यह क्यों आवश्यक है तथा इससे समाज को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत लोक अदालत एवं मीडिएशन की प्रक्रिया, उनके महत्व एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही मीडिएशन की अवधारणा को महाभारत के प्रसंगों से जोड़कर भी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में साइबर फॉड, उसके विभिन्न प्रकार एवं उससे बचाव के उपायों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिससे विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ी। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को कानून का सम्मान करने एवं उसका पालन करने की शपथ दिलाई गई तथा राज्यगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

जगदलपुर : खरीफ सीजन के लिए तैयारी शुरू : 25 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध, फार्मर आईडी पंजीयन की अपील

नील हरित काई और नैनो खादों से बढ़ेगी पैदावार

जगदलपुर (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में जिले में खरीफ वर्ष 2026 के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभाग ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के शोध के आधार पर किसानों से संतुलित उर्वरक उपयोग की अपील की है, जिसके तहत नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। नैनो यूरिया का निर्धारित दर पर दो बार छिड़काव करने से नत्रजन उर्वरक की खपत में 25 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है, वहीं नैनो डीएपी के माध्यम से बीजोपचार और छिड़काव करने पर फास्फोरस की मात्रा में भी 25 प्रतिशत की बचत संभव है। इस तकनीकी जानकारी के प्रचार-



प्रसार हेतु जिला प्रशासन द्वारा सहकारी समितियों और निजी केंद्रों पर पोस्टर और फ्लेक्सों भी चस्पा किए गए हैं। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले हेतु कुल 46,050 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से वर्तमान में 25,775 मीट्रिक टन का स्टॉक

उपलब्ध है। वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु भूमि आधारित नवीन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भविष्य में केवल फार्मर आईडी के माध्यम से

ही खाद का वितरण किया जाएगा। इसी क्रम में किसानों से अपील की गई है कि वे सीएससी या लैम्पस के माध्यम से अपना पंजीयन तत्काल पूर्ण करा लें।

खबर-खास

पटवारी की मनमानी उजागर :
नकल और नक्शा काटने के
नाम पर हितग्राही से मांगी
मोटी रकम और बीयरशिकायत के बाद प्रशासन हटकरत में, एसडीएम
ने जारी की नोटशीट डू जांच के आदेश

गरियाबंद (समय दर्शन)। जिले के में राजस्व विभाग द्वारा के एक पटवारी के कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है नकल और नक्शा काटने जैसे सामान्य सरकारी कार्य के एज में एक पटवारी द्वारा हितग्राही से लंबी रकम और बीयर की मांग किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीडित द्वारा पटवारी के संग मोबाइल में किए बात का ऑडियो रिकार्डिंग और रिश्त देते वीडियो के वायरल होने पर एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए नोटशीट जारी कर जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, एक हितग्राही द्वारा ब्लाक के ग्राम में अपने जमीन से संबंधित नकल और नक्शा निकलवाने के लिए संबंधित पटवारी हल्का नम्बर 28 के पास कामी चकर लगा चुका था। आरोप है कि पटवारी ने काम करने के एज में पहले तो टालमटोल किया, फिर खुले तौर पर मोटी रकम की मांग कर दी, और ये मांगी गई रकम आर आई और तहसीलदार तक को देने की बात कहा इतना ही नहीं, आरोप है कि पटवारी ने पैसे के साथ-साथ बीयर की भी डिमांड रख दी।

वही पटवारी से परेशान हितग्राही ने पटवारी द्वारा पैसे की मांग का वाइस रिकार्डिंग किया साथ ही कार्य के बदले पैसे देने का मोबाइल पर वीडियो रिकार्डिंग कर इसे वायरल कर दिया इन सबूतों के मिलते ही द्वारा एस डी एम अर्चना खलको इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पटवारी द्वारा ब्लाक के हल्का नम्बर 28 के पटवारी खेमचंद साहू के खिलाफ नोटशीट जारी कर दिए।

वही उक्त पटवारी की शिकायत करते हुए स्पष्ट रूप से बताया गया कि बिना सर्टिफिकेट के काम नहीं किया जा रहा और अवैध मांग लगाता बढ़ती जा रही है।

एसडीएम ने दिखाई सख्ती: शिकायत मिलते ही एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नोटशीट जारी कर जांच के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, संबंधित पटवारी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित पटवारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है।

राजस्व विभाग की छवि पर सवाल: इस घटना ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों और ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, साथ ही जिला प्रशासन हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनके समस्याओं का निदान कर रही है लेकिन एक पटवारी के मोनोपॉली के चलते आम जनता को छोटे-छोटे कामों के लिए भी चक्र काटने पड़ते हैं और कई मामलों में रिश्त की मांग आम बात बनती जा रही है।

इस प्रकार का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

पद का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने का मामला- यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपी पटवारी को निलंबन के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके और सरकारी व्यवस्था में भरोसा कायम रह सके।

इस विषय में द्वारा एस डी एम अर्चना खलको से बात करने पर उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं है, अभी आरोपी पटवारी को नोटिस दिया जा रहा है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई किया जायेगा।

पुलिस अधिकारियों को मिली
आधुनिक सुविधा

सुकमा। जिले के पुलिस अधिकारियों को बेहतर आवासीय एवं भोजन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस लाइन सुकमा में पुलिस अप्पर मेस का लोकार्पण किया। मेस लगभग 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह आधुनिक मेस पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और सुविधाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों और पुलिस अधिकारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में महिला आयोग सदस्य सुप्रीका सोरी, वरिष्ठ पार्टी प्रतिनिधि धनीराम बारसे, जिला पंचायत सदस्य कोरसा सबू, जिला पंचायत सदस्य हंगाराम मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष सुकमा हंगाराम मरकाम अन्य जनप्रतिनिधि सहित कमिश्नर ओमन सिंह, आईजी सुंदराम पी, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण, सीईओ जिला पंचायत मुकुन्द ठाकुर, डीएफओ अश्वयुक्त कुमार मौसल उपस्थित थे।

नवनिर्मित सर्वसुविधा संपन्न
सभागार का हुआ लोकार्पण

कवर्धा (समय दर्शन)। जनपद में शिक्षा संस्कार एवं विद्यार्थियों के प्रतिभा विकास को ध्येय मंत्र के रूप में अंगीकार करने वाली शिक्षण संस्था गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा हमेशा अपने सामाजिक सरोकारों एवं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे विद्यालय के विद्यार्थियों के अंतर्निहित प्रतिभा का समुचित विकास हो सके। इसी कड़ी में विद्यालय में संगीत उत्सव समारोह



के अंतर्गत अंतर्विद्यालयीन संगीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस प्रतियोगिता के कनिष्ठ और वरिष्ठ दो वर्ग थे। मीडिया प्रभारी ने

समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन- वंदन किया गया। प्राचार्य ने सभी का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगीत आत्मा की भाषा है जो अपनी सरसता से सभी को वशीभूत रखने की शक्ति रखती है। इसके बाद गुरुकुल पब्लिक स्कूल, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महाराजपुर, अभ्युदय स्कूल, अशोका पब्लिक स्कूल तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रतिभागियों द्वारा सरस

राजस्थानी व सूफ़ी भजन का गायन किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय में नवनिर्मित सर्व सुविधा संपन्न सभागार का भी लोकार्पण किया गया। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की।

कनिष्ठ वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल व वरिष्ठ वर्ग में अभ्युदय स्कूल ने बाजी मारी- इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथियों एवं निर्णायक मंडल के सदस्यों ने भी अपने उद्गार

व्यक्त किया। प्रबंधन समिति के वरिष्ठ निदेशक महावीर जैन ने कहा कि गुरुकुल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। विद्यार्थियों के शिक्षणोत्तर प्रतिभा विकास के लिए यह नवनिर्मित सभागार उन्हें दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ गायन के तौर पर कनिष्ठ वर्ग में प्रथम दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वितीय अभ्युदय स्कूल, तृतीय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय तथा वरिष्ठ वर्ग में प्रथम अभ्युदय स्कूल द्वितीय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय तथा तृतीय गुरुकुल पब्लिक स्कूल को पुरस्कृत किया गया।

पाँच दिवसीय सेवाकालीन विषय आधारित शिक्षक प्रशिक्षण संपन्न

कवर्धा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट महाराजपुर में एफ्फ्लएन अंतर्गत नवीन पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित ब्लैण्डेडमोड प्रशिक्षण दिनांक 07 से 11 अप्रैल तक 5 दिवसीय सेवाकालीन विषय आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिले के चारों विकास खण्ड कवर्धा, पण्डरिया, बोड़ला एवं सहसपुर लोहारा से कुल 48 शिक्षकों को खण्ड स्तर व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य टी.आर. साहू ने प्रशिक्षण को बहुत ही उपयोगी बताते हुए प्रशिक्षणार्थियों को सक्रियता से प्रशिक्षण लेने हेतु निर्देशित किया। डाइट के शिक्षण प्रभारी श्री पांडे ने कहा कि नवीन पाठ्यपुस्तक आधारित एफ्फ्लएन. प्रशिक्षण वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यवहारिक, छत्र-तरीके एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक न केवल विषयवस्तु की गहराई को समझ पाएंगे, बल्कि उसे रोचक एवं सरल तरीके से विद्यार्थियों तक पहुँचाने में भी सक्षम होंगे। यह पहल निश्चित रूप से शिक्षण की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगी। संस्था के सहायक प्राध्यापक आरएस साहू ने भी शिक्षकों को



संबोधित किया। रामचरित सोलंकी ने बताया कि इस प्रशिक्षण में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यपुस्तकों में हुए बदलाव, शिक्षण के नए तकनीक के साथ स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ एफएस, स्टेट कैरीकूलम प्रैमवर्क तथा फउण्डेशनल स्टेज के अंतर्गत विकसित नवीन शैक्षिक माध्यम, 21वीं सदी के कौशल, हिन्दी भाषा, गणित, हमारा अद्भुत संसार पर्यावरण, योगशिक्षा, बहुकक्षा शिक्षण, शिक्षक की भूमिका, मानसिक स्वास्थ्य, स्टेट कैरीकूलम प्रैमवर्क फउंडेशनल स्टेज, स्टेट कैरीकूलम प्रैमवर्क स्कूल एजुकेशन 2024, चार

खण्डीय रूपरेखा, अप्रोच, सीखने के प्रतिफल, बुनियादी गणित एवं भाषा की निपुणता, पंचपदीय शिक्षण प्रणाली, कर्तव्यों का क्रमिक हस्तारण, मैंने सीख लिया के स्थान पर आओ सीखें, चुनौती आधारित आंकलन, कला शिक्षा, नैतिक मूल्य एवं संस्कार, भारतीय संस्कृति, संगीत और राष्ट्रीय सर्वेक्षण और होलेस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आदि पर जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में राज्य स्तर व्यक्ति सुमित पाण्डेय, भरत कुमार डोरे, डी.आर.जी. (जिला स्तर समूह) कमलेश कुमार लांडे, अनीश शर्मा, प्रेमिशा शर्मा, श्रवण कुमार रजक ने रामचरित सोलंकी ने अपनी सहभागिता दी।

पीएमजीएसवाय के तहत गरियाबंद जिले को नई सड़क सौगात

18.08 किलोमीटर लंबी 7 सड़कों
पर 1423.65 लाख रुपये
का होगा निर्माण

17 अप्रैल को कलेक्टर सभा कक्ष
में वर्चुअल रूप से होगा भूमिपूजन

गरियाबंद (समय दर्शन)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में स्वीकृत 7 सड़कों की कुल लंबाई 18.08 किमी है। जिसकी कुल लागत 14 करोड़ 23 लाख 65 हजार रुपये है। निर्माण कार्य का भूमिपूजन 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे कलेक्टर सभा कक्ष में वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इस वर्चुअल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने वाले इन कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। जिसमें सांसद, विधायक, मीडिया प्रतिनिधि एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इससे दूरस्थ क्षेत्र को पक्की सड़क से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगा।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इसके अंतर्गत विकासखण्ड देवभोग के सुपेबेड़ा से परेवापाली तक सड़क की लंबाई 1.56 किलोमीटर बनेगी। जिसकी लागत 125.26 लाख रुपये है। इसी प्रकार

विकासखण्ड गरियाबंद के मरदाकला से कारीडोंगरी तक की लंबाई 3.30 किलोमीटर है। जिसकी लागत 272.44 लाख रुपये, रावनडिगगी से सेम्हरा तक की लंबाई 2.71 किलोमीटर जिसकी लागत 185.11 लाख रुपये है।

विकासखण्ड मैनपुर के मुड़गोलमाल से स्याहीडोंगरी तक की लंबाई 3.34 किलोमीटर है। जिसकी लागत 300.66 लाख रुपये, भाटीगढ़ से भटागांव तक की लंबाई 0.86 किलोमीटर 64.73 लाख रुपये, कोदोभांड से साल्हेभांड 2.49 किलोमीटर एवं 205.72 लाख रुपये तथा अडगडी (जरहीडीह) से कोसमबुडा 3.82 किमी एवं 269.63 लाख रुपये निर्धारित है।

फोर लेन सड़क निर्माण में बड़ा खेल! दिन-रात अवैध
मिट्टी खनन के बाद घटिया नाली निर्माण से खुली पोल

बिना अनुमति मिट्टी खुदाई, मानकों की
घटियां उड़ाकर हो रहा निर्माण

नाली निर्माण में न वाइडर, न
गुणवत्ता-ठेकेदार पर मेहरबान प्रशासन

गरियाबंद (समय दर्शन)। नगर में बन रही फोर लेन सड़क अब विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक बनती जा रही है। निर्माण कार्य के नाम पर खुलेआम चैन माउंटन मशीन के माध्यम से अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है और दिन-रात बिना किसी रोक-टोक के मिट्टी ढोकर सड़क में डाली जा रही है। वहीं सड़क किनारे बनाई जा रही नालियों की हालत देखकर साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। प्रशासन की चुपकी इस पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना रही है।

नगर में चल रहे फोर लेन सड़क निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के आसपास के क्षेत्रों से मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है रात के अंधेरे में भी ट्रैक्टर और हाइवा के जरिए मिट्टी का परिवहन लगातार जारी है, जिससे शासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे बनाई जा रही नालियों में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण कार्य में न तो वाइडर मशीन का उपयोग किया जा रहा है और न ही सीमेंट-कंक्रीट के निर्धारित अनुपात का



पालन किया जा रहा है। नाली की ढलाई पूरी तरह से मनमानी तरीके से की जा रही है, जिससे इसकी मजबूती और टिकाऊपन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर इसी तरह घटिया निर्माण कार्य चलता रहा तो कुछ ही महीनों में सड़क और नालियां टूट-पूट का वैध शिकार हो जाएंगी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके, जिम्मेदार अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने तक नहीं पहुंच रहे हैं।

प्रशासन पर सवाल: सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी अनियमितताओं के बावजूद प्रशासन मौन क्यों है? क्या ठेकेदार को किसी का संरक्षण प्राप्त है या फिर जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर आंख मूंदे बैठे हैं? यह मामला

सीधे-सीधे भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता की ओर इशारा कर रहा है। वहीं ये हो रहे सड़क निर्माण के पहले या बाद में कहीं भी सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जबकि उस सूचना बोर्ड में कार्य का नाम, लागत कार्य प्रारम्भ और पूर्ण होने की तिथि का उल्लेख होना था।

जनता की मांग: नगरवासियों ने इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कर पुनः निर्माण कराने की भी मांग उठ रही है। अगर समय रहते इस गंभीर मामले पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह फेर लेन सड़क आने वाले समय में जनता के लिए सुविधा नहीं, बल्कि परेशानी और भ्रष्टाचार की मिसाल बन जाएगी।

स्काई मेन्स विवर का छप्पर तोड़कर
नगदी समेत हजारों का सामान पार

कोरबा। जिले के कोयलांचल कुसमुंडा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां चोर लगातार सक्रियता दिखाते हुए एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सुस्त पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। चोरों का मुख्य निशाना दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान होता है, जिससे व्यवसायियों में भय व आक्रोश का माहौल है। बीती रात चोरों ने पुनः पुलिस को चुनौती देते हुए कुसमुंडा थानांतर्गत इमलीछापर चैक पर स्थित स्काई मेन्स विवर नामक दुकान का छप्पर तोड़ा और उसके भीतर प्रवेश कर कपड़ा, जूता व नगदी रकम को पार कर दिया।

Name Change

This is to inform to all that I am known by the name 'Jai Thomas Mannanal' in my all documents except in my wife's passport where the name is mentioned as Mrs. Lata Jai, Wife of Mr. Jai Thomas.

Hence, I hereby state that my name 'Jai Thomas Mannanal' is correct and the same to be incorporated in my wife's passport as 'Jai Thomas Mannanal' instead of 'Jai Thomas'.

Jai Thomas Mannanal

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
नया मुख्यालय मदन गांधी चौक, रायपुर फोन नं. 2535780, 90, फैक्स: 0771-2227395, E-mail: ee.electrical.rmc@gmail.com

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना
क्रमांक/47/विद्युत/न.पा.नि./2026 दि.16/04/2026

नगर पालिक निगम, रायपुर, विद्युत विभाग द्वारा निर्मांकित कार्य हेतु लो.नि.वि. एकल खिड़की प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत 'अ' वर्ग विद्युत ठेकेदारों / फर्मों से मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति के माध्यम से स्पीड पोस्ट से दिनांक 05/05/2026 को संध्या 4:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, प्राप्त सभी निविदाएँ उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख दिनांक 05/05/2026 को संध्या 05:00 बजे खोली जाएगी। कार्य हेतु निविदा प्रपत्र-अ निर्धारित राशि रु. 750.00 जमा कर दिनांक 04/05/2026 तक नगर पालिक निगम, विद्युत विभाग, मुख्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत राशि	अमानती राशि (रु)
1	शहर के मुख्यमार्गों के क्षतिग्रस्त हुये लाईटों का रिपेयरिंग कर प्रकाश व्यवस्था कार्य बाबत।	9,53,500.00	9550.00

उपरोक्त से निकलने वाले गीला और सूखा कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देना।
कार्यपालन अभियंता (विद्युत) नगर पालिक निगम, रायपुर

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

साहीवाल पशु नीलामी सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा, जिला दुर्ग में दिनांक- 24/04/2026 दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे से साहीवाल पशुओं को नीलाम किया जावेगा। समस्त इच्छुक पशुपालकों को नीलामी में बोली लगाकर पशु क्रय करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। नीलामी में बोली लगाने वाले को रुपये 500/- की धरोहर राशि जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर वापिस की जावेगी। नियम, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें, शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा, जिला दुर्ग से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

टीप- नीलामी में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को स्वयं का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर आई डी/अन्य शासकीय पहचान पत्र) को प्रति पंजीवन के समय जमा करना अनिवार्य है। नीलामी में किसी प्रकार का विवाद होने पर नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

दूरभाष- 0788-2990043, 8103533882
G-262700195/ 1
उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें शा.प.प्र. अंजोरा दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बालोद (छ.ग.)

निविदा क्र. 01/ले.शा./ज.मि./का.अ./लो.स्वा.या./खण्ड/2026 बालोद, दिनांक : 13-04-2026

ई - प्राक्चोरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना (Risk & Cost)

ऑनलाईन निविदाएं प्रपत्र-ए में प्रतिष्ठित दर पर नीचे उल्लेखित कार्य के लिये कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद द्वारा के एकीकृत पंजीवन व्यवस्था ई-रजिस्ट्रेशन की सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण - बालोद जिले के वि.खं. डौणडी के ग्राम पण्डेल में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम नल जल प्रदाय योजना का कार्य।

नि.सू. क्र./ सिस्टम	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1/ 01/188819	विकासखंड डौणडी के ग्राम पण्डेल में टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार तथा अन्य कार्य (शेड्यूल के अनुसार)।	रु. 48.45 लाख

1. बिड सर्वमिशन प्रारंभ की तिथि - 14/04/2026
2. बिड सर्वमिशन की अंतिम तिथि - 02/05/2026
उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञापन निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्चोरमेंट वेब पोर्टल <http://eproc.cgstate.gov.in> दिनांक 14/04/2026 से एवं कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद जिला - बालोद (छगो)

G-262700185 / 4

